

>

Title: Regarding Government Business during the week commencing Monday, the 15 of July, 2019 and submissions made by the Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, I rise to announce that Government Business

during the week commencing Monday, the 15th of July, 2019 will consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains (i) Further discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Railways for 2019- 20; (ii) Consideration and passing of the Central Universities (Amendment) Bill, 2019; and (iii) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Road Transport and Highways for 2019-20.]*
2. Discussion & Voting on Demands for Grants of the following Ministries for 2019-20:-
 - (i) Rural Development and Agriculture and Farmers' Welfare
 - (ii) Youth Affairs and Sports

3. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2019-20.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No.2) Bill relating to the Demands for Grants for 2019-20.
5. Consideration and passing of the Finance (No.2) Bill, 2019.
6. Consideration of passing of the following Bills:-
 - (i) The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019.
 - (ii) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019.
 - (iii) The National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019
 - (iv) The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019
 - (v) The Consumer Protection Bill, 2019
 - (vi) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ । अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आए मीणा और मीना दोनों को ही एक समान माना जाए ।
2. मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान बांसवाड़ा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है । मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि मानगढ़ धाम को जनजातीय राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें ।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय अध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. बिहार के औरंगाबाद बिहटा रेलवे का निर्माण कार्य केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना को जनहित में यथाशीघ्र कराया जाए।

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): I request you that the following matter may be included in the next week's List of Business:

1. In 1965, the Lokur Committee appointed by the Central Government had recommended that the Narikuravar alias Kuruvikkarar community be given ST status. I urge upon the Union Government to bring the constitution (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) orders (Amendment) Bill 2019 to extend the Scheduled Tribes status to Narikuravars.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. नागौर जिले में सैनिक परिवारों की संख्या को देखते हुए सैनिक स्कूल खोलने पर विचार किया जाए।
2. नागौर जिले के विस्तृत भू-भाग तथा जनसंख्या को देखते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में महाराजगंज एवं चैनवा रेलवे स्टेशन के साथ खाली पड़ी जमीन/भूमि पर रैक प्वाइंट बनाने पर विचार किया जाए ।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सारण छपरा जिला, बिहार के जलालपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं एनआईईएलआईटी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खुलवाने पर विचार किया जाए ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में केन्द्रीय विद्यालय, राजगीर के इंटर की कक्षा में अभी कामर्स एवं विज्ञान विषय की पढ़ाई हो रही है । परंतु इंटर में आर्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है । मेरी माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय राजगीर में शिक्षा सत्र, 2019-20 से ही आर्ट्स की पढ़ाई इंटर की कक्षा में प्रारंभ की जाए ।
2. बिहार में बीपीएल के नए मापदंड के कारण मात्र 60 लाख परिवारों को ही सूची में शामिल किया गया है, जबकि 1 करोड़ 33 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत करता हूँ:

1. राजस्थान के सीकर, झुंझुनू जिलों के किसानों को सरकारी एजेंसी द्वारा नकली डीएपी बेचने के संबंध में चर्चा कराई जाए ।
2. सीकर झुंझुनू जिलों सहित राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या पर चर्चा कराने के संबंध में ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business:

1. Fatal pedestrian accidents on NH4 stretch from Bavdhan to Ravet of Maharashtra. I request the Government to take cognizance of urgency and construct foot overbridges, underpasses to ensure pedestrian's safety.
2. There is high unemployment and lack of jobs in the country. There is also lack of sufficient work under MGNREGA in drought hit regions of Maharashtra. I urge the Centre to release sufficient funds for drought.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business: -

1. The proposed Kendriya Vidyalaya Kottarakkara, Kollam district, Kerala should be commenced from this academic year.
2. Pathanapuram is one of the Taluks of my Parliamentary constituency in Kerala. Pathanapuram Taluk is the most backward and thickly forested area. There is a proposal to set up an FM Radio Station there, and I urge the Government to take action in this regard.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM) : Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business: -

1. Denial of admission to the wards of insured persons in ESI medical colleges due to the verdict of Madras High Court.
2. Revival package for cashew industry giving relief to lakhs of poor cashew workers.

12.10 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES